अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 202 | श्री विजय पुरम, बुधवार, 29 जुलाई 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रुपए

चिकित्सीय आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए कृपया 112 पर डायल करें।

मुख्य सचिव ने 'जम्स ऑफ इंडिया' चैलेंज का किया शुभारंभ

उभरते डिजिटल रचनाकारों को वैश्विक मंच पर द्वीपों की विरासत प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

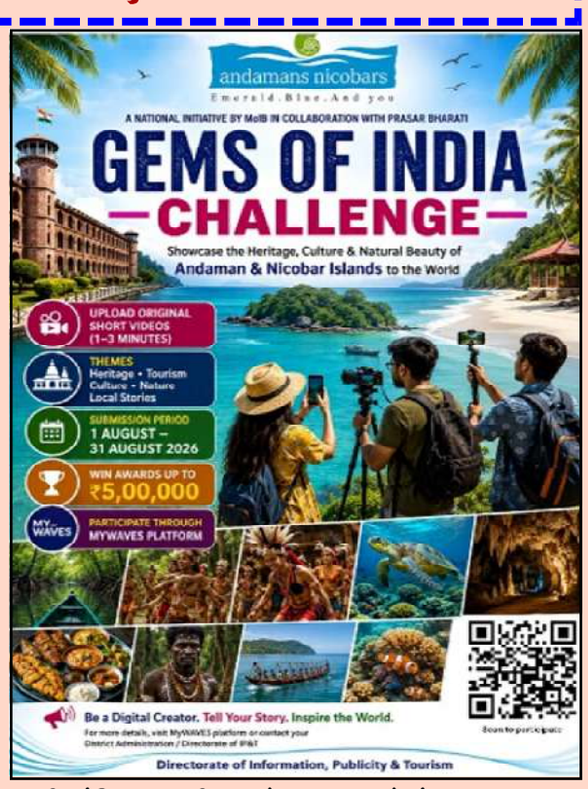

द्वीपसमूह की युवा प्रतिभाओं को वैश्विक मंच उपलब्ध कराने तथा स्थानीय "कॉन्सर्ट इकोनॉमी" को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, भा.प्र.से., ने आज सचिवालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान आधिकारिक रूप से "जम्स ऑफ इंडिया" चैलेंज का शुभारंभ किया।

'जम्स ऑफ इंडिया' चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती के सहयोग से संचालित एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ज़िले से उभरते डिजिटल रचनाकारों की पहचान करना तथा उन्हें भारत की अनूठी संस्कृति, विरासत एवं पर्यटन क्षमता को वास्तविक डिजिटल कहानी–कथन के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उल्लेखनीय है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह देशभर में चयनित केवल छह राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में से एक है, जिसे इस विशेष पायलट चरण में भाग लेने का अवसर मिला है।

शुभारंभ अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि यह पहल द्वितीय विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2027 के व्यापक ढांचे का हिस्सा है, जिसका आयोजन फरवरी, 2027 में मुंबई में प्रस्तावित है। उन्होंने द्वीपों के युवाओं एवं डिजिटल रचनाकारों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया ताकि वे क्षेत्र की "अनमोल धरोहरों" को दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत कर सकें, जिनमें स्थानीय परंपराएं, दुर्लभ कला रूप तथा अद्भुत पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल शामिल हैं।

चैलेंज के प्रमुख विवरण:

कौन भाग ले सकता है: नागरिक, विशेष रूप से युवा एवं उभरते हुए डिजिटल सामग्री रचनाकार।

सामग्री के विषय: संस्कृति एवं विरासत, स्थानीय व्यंजन, लोक परंपराएं, प्रदर्शन कलाएं, प्रकृति/पारिस्थितिकी पर्यटन तथा प्रेरणादायक स्थानीय कहानियां।

प्रारूप: लघु वीडियो, रील एवं वीडियो ब्लॉग, जिनकी सुझाई गई अवधि 1 से 3 मिनट तक होगी।

कैसे भाग लें: प्रतिभागी सीधे https://www.wavespb.com/mwlink/CN31Vwv के माध्यम से चैलेंज में भाग ले सकते हैं अथवा वेव्स ओटीटी मंच के माईवेव्स अनुभाग के माध्यम से अपनी मौलिक सामग्री अपलोड कर सकते हैं।

प्रस्तुति की समय–सीमा: पायलट चरण के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अवधि 1 अगस्त से 31 अगस्त, 2026 तक निर्धारित की गई है।

सम्मान एवं पुरस्कार: उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को प्रोत्साहित करने के लिए चैलेंज में आकर्षक पुरस्कार व्यवस्था रखी गई है:

- जिला स्तर: प्रत्येक ज़िले में अधिकतम 20 पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार की राशि 50,000 रुपये।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर: ज़िलों से चयनित श्रेष्ठ प्रविष्टियों के लिए 2,00,000 रुपये का पुरस्कार।
- राष्ट्रीय स्तर: उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अधिकतम 5,00,000 रुपये तक के पुरस्कार।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि स्थानीय प्रतिभागियों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रशासन नोडल तकनीकी भागीदार वेंस्यस्को टेक्नोलॉजीज के साथ समन्वय करेगा तथा पंजीकरण एवं सामग्री अपलोड करने की प्रक्रिया पर ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन सत्र आयोजित किए जाएंगे।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ज़िला प्रशासन एवं माई भारत स्वयंसेवकों के साथ मिलकर कार्य करेगा, ताकि द्वीपों की प्रत्येक रचनात्मक आवाज़ को राष्ट्रीय मंच पर अपनी कहानी प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके। अधिक जानकारी के लिए रचनाकारों को ऊपर दिए गए आधिकारिक माईवेव्स मंच के लिंक पर जाने अथवा सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

मोहनपुरा विद्यालय में स्वच्छता एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में स्वच्छता एवं साफ–सफाई की स्थिति का निरीक्षण करने के उद्देश्य से आज पद्मश्री से विभूषित एवं स्वच्छ भारत मिशन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के ब्रांड एंबेसडर श्री नरेश चंदर लाल ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुरा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ संवाद कर विद्यालय परिसर के साथ–साथ अपने–अपने मोहल्लों एवं समाज में भी स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया। श्री लाल ने विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए उन्हें

शेष पृष्ठ 4 पर

'अनिम्स' में पॉश पर जागरूकता लाई गई

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स) में 21 जुलाई, 2026 को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पॉश) विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों, जूनियर रेजिडेंट्स, इंटर्न्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मियों सहित 70 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ 'अनिम्स' की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की अध्यक्षा डॉ. रूबी थॉमस के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए ऐसे कार्यस्थल के निर्माण के महत्व पर बल दिया, जहां प्रत्येक कर्मचारी स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित तथा मूल्यवान महसूस करे।

सभा को संबोधित करते हुए 'अनिम्स' के निदेशक प्रो. (डॉ.) मुकेश त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्यस्थल किसी भी संस्थान की आधारशिला है, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, जहां कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रति जागरूकता, पारस्परिक सम्मान, व्यावसायिकता तथा जवाबदेही की संस्कृति विकसित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

जीबी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एम. के. साहा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने इस पहल की

शेष पृष्ठ 4 पर

कैम्पबेल बे में एलपीजी आपूर्ति बहाल करने के लिए प्रशासन ने तेज किए प्रयास

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

सुदूर दक्षिणी द्वीपसमूह के ग्रेट निकोबार के कैम्पबेल बे के निवासियों को सूचित किया जाता है कि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा कैम्पबेल बे में नियमित एलपीजी आपूर्ति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से नियमित जहाज़ सेवाओं में व्यवधान के कारण घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हुई है।

यह भी सूचित किया जाता है कि द्वीपसमूह में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा अपने अधिकृत एलपीजी वितरक के माध्यम से किया जाता है। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की ओर से नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय द्वारा द्वीपसमूह में एलपीजी की उपलब्धता एवं वितरण की निरंतर निगरानी की जाती है।

निर्धारित जहाज़ सेवाओं में व्यवधान के कारण पिछले कुछ महीनों से कैम्पबेल बे तक एलपीजी सिलेंडरों का परिवहन नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप वहां भंडार में कमी आई और एलपीजी सिलेंडरों की अस्थायी कमी उत्पन्न हुई।

कैम्पबेल बे के निवासियों को हो रही असुविधा को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल इस मामले को भारतीय नौसेना के समक्ष उठाया। भारतीय नौसेना, अण्डमान तथा निकोबार कमान, आईओसीएल तथा अन्य संबंधित हितधारकों के समन्वित प्रयासों से 250 भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों की विशेष खेप सफलतापूर्वक कैम्पबेल बे पहुंचाई गई, जिससे उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली।

चूंकि कैम्पबेल बे में एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता अभी भी उपलब्ध कराई गई मात्रा से अधिक बनी हुई है, इसलिए निदेशालय ने एक बार फिर भारतीय नौसेना से अतिरिक्त 250 भरे हुए एलपीजी सिलेंडरों की खेप के परिवहन के लिए सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। सिलेंडरों को भारतीय नौसेना की परिचालन व्यवहार्यता के आधार पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही अगस्त के प्रथम सप्ताह के

शेष पृष्ठ 4 पर

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय चिड़ियाटापू में "वर्षावन पक्षी अवलोकन मार्ग" का आयोजन करेगा

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल द्वारा प्रारंभ किए गए पर्यटन मेलों/त्योहारों/कार्यक्रमों के कैलेंडर 2026–27 के अंतर्गत, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, पर्यावरण एवं वन विभाग और एवियन क्लब के सहयोग से, 1 अगस्त, 2026 (शनिवार) को सुबह 8 बजे से दक्षिण अण्डमान के चिड़ियाटापू जैविक उद्यान में "वर्षावन पक्षी अवलोकन मार्ग" (रेनफॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल) का आयोजन कर रहा है।

इस आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण–पर्यटन को बढ़ावा देना और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध पक्षी विविधता और निर्मल वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रतिभागियों को अनुभवी विशेषज्ञों और पक्षी अवलोकन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में द्वीप के सबसे खूबसूरत पक्षी दर्शन स्थलों में से एक का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, साथ ही वे क्षेत्र की स्थानिक और प्रवासी पक्षी प्रजातियों और जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में भी जानेंगे। निदेशालय प्रकृति प्रेमियों, पक्षी प्रेमियों, छात्रों, फोटोग्राफरों, ट्रैवल एजेंटों, पर्यावरण–पर्यटन से जुड़े हितधारकों और आम जनता को इस अनूठे प्रकृति भ्रमण में भाग लेने और द्वीप की उल्लेखनीय प्राकृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक प्रतिभागी सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय में अपना नाम पहले से पंजीकृत करा सकते हैं। भागीदारी पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी, बशर्ते सीटें उपलब्ध हों। निदेशालय सभी प्रकृति प्रेमियों को इस ज्ञानवर्धक अनुभव का हिस्सा बनने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ज़िम्मेदार एवं टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए हार्दिक आमंत्रित करता है।

लिटिल अण्डमान के ब्रेक वाटर, ओंगी टेकरी तथा हरमिंदर बे में लगा पशु स्वास्थ्य शिविर

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा 27 एवं 28 जुलाई, 2026 को लिटिल अण्डमान के ब्रेक वाटर, ओंगी टेकरी तथा हरमिंदर बे क्षेत्रों में पशु स्वास्थ्य शिविरों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन शिविरों का उद्देश्य द्वीप के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले किसानों तथा जनजातीय समुदायों को उनके घर–द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना था।

27 जुलाई, 2026 को हटबे के ब्रेक वाटर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान कुल 253 पशुओं का उपचार किया गया। प्रजातिवार विवरण इस प्रकार है: गौवंश–15, बकरियां–24, सूअर–185 तथा कुत्ते–13।

28 जुलाई, 2026 को दो अलग–अलग स्वास्थ्य शिविर

शेष पृष्ठ 4 पर

मायाबंदर कॉलेज में मना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों का शुभारम्भ

मायाबंदर, 28 जुलाई

महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय (एमजीजीसी), मायाबंदर, उत्तर व मध्य अण्डमान की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाइयों द्वारा 28 जुलाई, 2026 को सुबह 10.30 बजे महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान आयोजित कर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों का शुभारम्भ भी किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य, डॉ. आर. वी. आर. मूर्ति के अध्यक्षीय संबोधन से हुआ। उन्होंने शैक्षणिक सत्र के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों का औपचारिक उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सामुदायिक सेवा

शेष पृष्ठ 4 पर

मत्स्य पालकों को इंडियन मेजर कार्प प्रजाति के मीठे पानी के मत्स्य चारे वितरित किए जाएंगे

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग के अंतर्गत नयागांव स्थित मीठे पानी के मत्स्य चारे उत्पादन फार्म द्वारा इंडियन मेजर कार्प (आईएमसी) प्रजाति के मीठे पानी के मत्स्य चारे का उत्पादन किया गया है। ये मत्स्य चारे वितरण के लिए तैयार हैं तथा दक्षिण अण्डमान ज़िले की फरारगंज तहसील के विभिन्न पंचायतों के इच्छुक मत्स्य पालकों को 30 जुलाई, 2026 को निम्नलिखित निर्धारित समयानुसार वितरित किए जाएंगे:—

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वितरण स्थल	वितरण का संभावित समय
1.	ग्राम पंचायत बृंदाबन	ग्राम पंचायत कार्यालय, बृंदाबन	सुबह 8.30 बजे
2.	ग्राम पंचायत स्टीवर्टगंज (बम्बूफ्लाट के मत्स्य पालकों सहित)	ग्राम पंचायत कार्यालय, स्टीवर्टगंज	सुबह 9.30 बजे
3.	ग्राम पंचायत विम्बर्लीगंज एवं कन्यापुरम	ग्राम पंचायत कार्यालय, विम्बर्लीगंज	सुबह 10.30 बजे
4.	ग्राम पंचायत मनारघाट	ग्राम पंचायत कार्यालय, मनारघाट	सुबह 11.30 बजे
5.	ग्राम पंचायत शोल बे	ग्राम पंचायत कार्यालय, शोल बे	दोपहर 1 बजे

प्राप्त विज्ञप्ति में इच्छुक मत्स्य पालकों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित वितरण स्थल से मीठे पानी के मत्स्य चारे प्राप्त करें। फ्राई आकार के मत्स्य चारे के प्रत्येक ऑक्सीजनयुक्त पैकेट की कीमत 135 रूपए निर्धारित की गई है। इसका भुगतान वितरण स्थल पर ही करना होगा।

एएलसी ने उपभोक्ता हिमायती में ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

अण्डमान लॉ कॉलेज (एएलसी) में तीन महीने का उपभोक्ता हिमायती प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हो गया है। देशव्यापी उपस्थिति वाला उपभोक्ता अधिकार समूह (सीएजी) अण्डमान लॉ कॉलेज के छात्रों के लिए विशेष रूप से यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. पी.वी.एन. सरमा के अनुसार, यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है और सभी अंतिम वर्ष के छात्र इसमें नामांकित हैं। सीएजी ने उपभोक्ता मुकदमेबाज़ी के क्षेत्र में भावी विधि स्नातकों को सहजता और आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षित करने के अपने मिशन के तहत इस पाठ्यक्रम को तैयार किया है। पाठ्यक्रम पूरा होने पर, छात्र को एक ई—प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित सात विषय विशेषज्ञों ने छात्रों को ऑनलाइन सत्र देने पर सहमति व्यक्त की है। उपभोक्ता अधिकार समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पी. वी.वी.एस. मूर्ति ने बताया कि सत्र प्रत्येक शनिवार शाम या रविवार सुबह आयोजित किए जाएंगे। पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, डॉ. मूर्ति ने प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर उन उपभोक्ताओं की सेवा करें जो अक्सर बाज़ार में शोषित और कमज़ोर वर्ग होते हैं। उन्होंने कहा, "जागरूकता से सशक्तिकरण प्राप्त होता है।" इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार श्री वाई. रामकृष्ण ने दिया। रामकृष्ण ने 'पेशेवर नैतिकता और न्यायालय शिष्टाचार' पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने छात्रों की शंकाओं और प्रश्नों का स्पष्टीकरण किया। सुश्री अलकामा को संकाय समन्वयक और सुश्री आलिया मजीद को छात्र समन्वयक नियुक्त किया गया।

'अनिम्स' में पॉश पर जागरूकता लाई

पृष्ठ 1 का शेष

सराहना करते हुए सभी स्वास्थ्यकर्मियों से उत्पीड़न एवं भेदभाव से मुक्त कार्यस्थल बनाए रखने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।

तकनीकी सत्र का संचालन प्रमाणित पॉश मास्टर प्रशिक्षक एवं परामर्शदाता तथा राइट्स फॉर ऑल (आरएफए) की अध्यक्षा श्रीमती रुबीना ख़ातिब सिद्दीक़ी ने किया। वे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थानों में पॉश विषयक जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करती रही हैं।

उन्होंने व्यावहारिक उदाहरणों तथा कार्यस्थल की वास्तविक परिस्थितियों के माध्यम से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की ज़िम्मेदारियों तथा सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समावेशी कार्य वातावरण विकसित करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

यह सत्र अत्यंत संवादात्मक रहा तथा प्रतिभागियों ने इसे सराहा। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों एवं रेजिडेंट्स ने सक्रिय सहभागिता करते हुए प्रश्नोत्तर सत्र में व्यावहारिक प्रश्न पूछे तथा कार्यस्थल से जुड़े अपने अनुभव एवं विचार साझा किए। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों द्वारा पॉश अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षित, सम्मानजनक एवं समानतापूर्ण कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की पुनः प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेस्डर

पृष्ठ 1 का शेष

किसी भी प्रकार के नशीले अथवा शरीर एवं मस्तिष्क को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी।

उन्होंने विद्यार्थियों को विद्यालय में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने पुस्तकालय में नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करने पर भी ज़ोर दिया। विद्यालय की प्रभारी शिक्षिका श्रीमती सुनीता शर्मा ने इस दौरे के दौरान स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर के साथ सहभागिता की। यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य,

अनुशासन तथा सकारात्मक जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

मायाबंदर कॉलेज में मना विश्व प्रकृति

पृष्ठ 1 का शेष

गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के प्रतीकात्मक रूप में डॉ. आर. वी. आर. मूर्ति ने पहला पौधा रोपित किया, जिससे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों एवं प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की प्रेरणा मिली।

राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी, डॉ. कंडिमुथु ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन तथा निरंतर वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके उपरांत, महाविद्यालय के संकाय सदस्यों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भागीदारी की। इस दौरान महाविद्यालय परिसर में लगभग 50 पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरणीय सततता के प्रति उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं स्टाफ ने

उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे वृक्षारोपण अभियान एक सार्थक एवं सफल पहल सिद्ध हुआ। कार्यक्रम का समन्वयन महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारियों डॉ. कंडिमुथु तथा डॉ. जी. गॉडसन बेदियाह द्वारा किया गया।

लिटिल अण्डमान के ब्रेक वाटर, ओंगी

पृष्ठ 1 का शेष

आयोजित किए गए। हटबे के ओंगी टेकरी में कुल 249 पशुओं का उपचार किया गया, जिनमें गौवंश—28, बकरियां—48, कुक्कुट—163 तथा कुत्ते—10 शामिल थे। इसी दिन हरमिंदर बे में एक अन्य स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जहां 517 पशुओं का उपचार किया गया। हरमिंदर बे में प्रजातिवार विवरण इस प्रकार रहा: बकरियां—49, सूअर—150, कुक्कुट—291 तथा कुत्ते—27।

इन तीनों शिविरों के दौरान कुल 1,019 पशुओं को उपचार एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की गईं। पशु चिकित्सा दलों द्वारा सामान्य स्वास्थ्य जांच, बीमार पशुओं का उपचार, कृमिनाशन तथा पशुधन के समग्र स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में सुधार के लिए अन्य आवश्यक चिकित्सीय उपाय किए गए।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रकार के जनसंपर्क कार्यक्रम दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचने, समय पर पशु चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने तथा पशुपालन एवं कुक्कुट पालन पर निर्भर स्थानीय किसानों की

आजीविका को सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग नियमित स्वास्थ्य शिविरों तथा क्षेत्रीय स्तर पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों के माध्यम से द्वीपसमूह में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय में भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डॉलीगंज, श्री विजय पुरम में 23 जुलाई, 2026 को शाम 3 बजे भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस अभ्यास का आयोजन आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), अण्डमान तथा निकोबार पुलिस, अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से किया गया। निदेशालय की आपदा संबंधी तैयारियों का आकलन करने तथा बड़े भूकंप की स्थिति में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिक्रिया प्रणाली का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कृत्रिम भूकंप की परिकल्पित स्थिति तैयार कर इस अभ्यास का आयोजन किया गया।

मॉक ड्रिल की शुरुआत भूकंप आपातकालीन स्थिति को सक्रिय किए जाने के साथ हुई। आपातकालीन सायरन बजते ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निर्धारित "झुकें, ढकें और पकड़कर रहें" प्रक्रिया का तुरंत पालन किया। कृत्रिम झटके समाप्त होने के बाद निदेशालय की घटना प्रतिक्रिया टीमों ने निकासी प्रक्रिया प्रारंभ की तथा सभी कर्मचारियों को चिन्हित निकासी मार्गों से सुरक्षित रूप से निर्धारित एकत्रीकरण स्थल तक पहुंचाया।? अभ्यास के दौरान यह मान लिया गया कि कुछ कर्मचारी घायल हो गए हैं तथा भवन के भीतर फंसे हुए हैं। खोज एवं बचाव दलों ने एनडीआरएफ, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस और अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सहयोग से व्यवस्थित खोज एवं बचाव अभियान चलाकर परिकल्पित पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा टीम ने घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया तथा अभ्यास की परिकल्पित स्थिति के अनुसार आगे के

चिकित्सीय प्रबंधन के लिए उन्हें स्थानांतरित किया।

मॉक ड्रिल का समापन समीक्षा सत्र के साथ हुआ, जिसमें सहभागी विभागों के पर्यवेक्षकों ने अभ्यास की प्रमुख उपलब्धियों, अवलोकनों तथा सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। एनडीआरएफ के उप कमांडेंट तथा अन्य अधिकारियों ने अद्यतन आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाए रखने, नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने, आपातकालीन उपकरणों की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करने तथा कर्मचारियों में जागरूकता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया, ताकि भूकंप जैसी आपात स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इस मॉक ड्रिल के सफल आयोजन में आपदा प्रबंधन निदेशालय, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), अण्डमान तथा निकोबार पुलिस, अण्डमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किए गए सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता की सराहना की। विभाग ने कहा कि उनके बहुमूल्य सहयोग से विभाग में भूकंप संबंधी तैयारियों को सुदृढ़ करने तथा आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

एनकॉल ने संसाधन व्यक्तियों व अतिथि संकाय सदस्यों की अनंतिम सूची अपलोड की

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

अण्डमान कॉलेज (एनकॉल) ने शैक्षणिक सत्र 2026—27 के लिए संसाधन व्यक्तियों व अतिथि संकाय सदस्यों की अनंतिम सूची अपलोड कर दी है। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि संसाधन व्यक्तियों (अतिथि संकाय) का अनंतिम पैनल कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अभ्यर्थी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट ीजजचेरूध्ध ancol.andaman.gov.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यदि शैक्षणिक सत्र 2026—27 के लिए संसाधन व्यक्तियों (अतिथि संकाय) के अनंतिम पैनल के संबंध में कोई दावा एवं आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी विभिन्न विषयों में संसाधन व्यक्तियों व अतिथि संकाय सदस्यों के पैनल को अंतिम रूप देने के लिए अपने दावे प्राचार्य कार्यालय, एनकॉल में अथवा कॉलेज के ई—मेल andamancollege@gmail.com के माध्यम से 31 जुलाई, 2026 को शाम 4.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

राजकीय पॉलिटेक्निक, डिगलीपुर में संविदा पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

राजकीय पॉलिटेक्निक (बहुशिल्प संस्थान), डिगलीपुर, उत्तर अण्डमान में विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए अनंतिम रूप से पात्र घोषित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:—

तिथि	समय	परीक्षा	परीक्षा स्थल
04.08.2026	सुबह 10 बजे—दोपहर 12 बजे तक	व्याख्याता (सिविल, सीएसई एवं गणित) के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	सीबीटी प्रयोगशाला
05.08.2026	सुबह 10 बजे—दोपहर 12 बजे तक	प्रयोगशाला तकनीशियन (सिविल एवं सीएसई) के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	
06.08.2026 से आगे	सुबह 9 बजे—सायं 6 बजे तक	व्याख्याता (सिविल एवं सीएसई) के लिए कौशल परीक्षा	सीबीटी प्रयोगशाला (सीएसई) तथा सिविल इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि पंजीकृत अभ्यर्थियों को शीघ्र ही उनके प्रवेश पत्र ई—मेल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकालें तथा उसमें दिए गए सभी निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से चयन की गारंटी नहीं होगी। अंतिम नियुक्ति भर्ती नियमों (आरआर) के अनुसार निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी।

अंतर विद्यालयीय उच्च प्राथमिक स्तर फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता

बालक वर्ग में केईएमएस तथा बालिका वर्ग में स्कूल लाइन स्कूल विजयी

श्री विजय पुरम, 28 जुलाई

उप शिक्षा कार्यालय, दक्षिण अण्डमान द्वारा आयोजित अंतर विद्यालयीय उच्च प्राथमिक स्तर बालक एवं बालिका फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता 2026—27 के फाइनल मुकाबले आज 28 जुलाई, 2026 को उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। प्रतियोगिता में दक्षिण अण्डमान के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने पूरे जोश एवं खेल भावना के साथ भाग लिया।

फाइनल मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन तथा टीम भावना का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यालयों के शिक्षकों, छात्र—छात्राएं तथा खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, जिससे मैदान में रोमांचक वातावरण बना रहा। भातूबस्ती स्कूल के मैदान में खेले गए फाइनल मैच के परिणाम के अनुसार बालक वर्ग में एसएसएस केईएमएस ने पीएम श्री जीएसएसएस प्रोथरापुर को 01—00 गोल से पराजित किया तथा बालिका वर्ग में जीएसएसएस स्कूल लाइन ने जीएसएसएस भातूबस्ती को 02—01 गोल से पराजित किया। बालक एवं बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबलों

में टीमों ने शानदार टीम भावना, खेल भावना तथा दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए रोमांचक प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत की। यहां प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार फाइनल मुकाबलों के अवसर पर शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक (खेल) श्री इरशाद अहमद, सहायक निदेशक (खेल) श्री बिश्वनाथ सेन तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भातूबस्ती के प्रधानाचार्य श्री दासन पुष्पराजन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बालक एवं बालिका दोनों वर्गों की विजेता तथा उप विजेता टीमों को सम्मानित कर पुरस्कृत किया।

कैम्पबेल बे में एलपीजी आपूर्ति

पृष्ठ 1 का शेष

दौरान एमवी चुगलम के माध्यम से लगभग 200 एलपीजी सिलेंडरों के परिवहन के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, एमवी मानव स्टार तथा एमवी शक्ति की निर्धारित यात्राओं के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडरों के परिवहन के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक पर्याप्त संख्या में एलपीजी सिलेंडर कैम्पबेल बे पहुंच जाएंगे, जिससे क्षेत्र में एलपीजी की सामान्य उपलब्धता बहाल होने की संभावना है।

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने इस आवश्यक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने में समय पर सहयोग एवं निकट समन्वय प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना और अण्डमान निकोबार कमान के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। प्रशासन ने कैम्पबेल बे के निवासियों को आश्वस्त किया है कि सामान्य एलपीजी आपूर्ति शीघ्र बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन—229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

सूचना

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने वाइपर एवं एंडरसन द्वीप के लिए एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएँ (IIMPs) तैयार करने का कार्य नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एन.सी.एस.सी.एम) / (NCSCM), चेन्नई को सौंपा है। यह कार्य द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (ICRZ) अधिसूचना, 2019 के अनुसार किया जा रहा है।

एन.सी.एस.सी.एम. ने वाइपर एवं एंडरसन द्वीप के प्रारूप आई.आई.एम.पी, तटीय भूमि उपयोग मानचित्र तथा भू–आकृति विज्ञान मानचित्र प्रस्तुत किए हैं और आम जनता एवं हितधारकों से सुझाव एवं टिप्पणियाँ आमंत्रित की हैं। ये मानचित्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (https://andamannicobar.gov.in/) तथा पर्यावरण एवं वन विभाग (https://forest.and.nic.in/), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

सॉफ्ट कॉपी विभिन्न कार्यालयों में भी उपलब्ध कराई गई है, जिनमें ए.एन.सी.जेड.एम.ए, के अध्यक्ष (मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन), सदस्य सचिव, ए.एन.सी.जेड.एम.ए., {एपीसीसीएफ (सी.आर.जेड. एण्ड एफ.सी) वन सदन, हैडो,} उपायुक्त (दक्षिण अण्डमान), उपायुक्त (मध्य एवं उत्तर अण्डमान), प्रभागीय वन अधिकारी (दक्षिण अण्डमान), प्रभागीय वन अधिकारी (मायाबंदर), अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मध्य एवं उत्तर अण्डमान, सहायक आयुक्त (मुख्यालय) (दक्षिण अण्डमान), सदस्य सचिव (प्रदूषण नियंत्रण समिति), निदेशक (कला एवं संस्कृति), निदेशक (सूचना, प्रचार और पर्यटन) तथा निदेशक (जनजातीय कल्याण विभाग), और तहसीलदार (श्री विजय पुरम), तहसीलदार (मायाबंदर), एवं रेंज अधिकारी (टुसनाबाद), रेंज अधिकारी (टुगापुर), के कार्यालय शामिल हैं।

संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने विचार, टिप्पणियाँ, सुझाव तथा वर्तमान या प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण, साथ ही अगले 10 वर्षों में होने वाले विकास, मास्टर प्लान, आदि का विवरण, यदि कोई हो, भौगोलिक संदर्भित Shapefiles (ArcGIS/ Shapefile/KML प्रारूप), सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ए.पी.सी.सी.एफ. (सी.आर.जेड एण्ड एफ.सी.)} वन सदन, हैडो, श्री विजय पुरम के कार्यालय में या apccf-crzfc.an@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से जमा करें।

सुझाव एवं टिप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय हितधारक ऊपर उल्लिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध ICRZ अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों का संदर्भ ले सकते हैं।

सदस्य सचिव,
अण्डमान तथा निकोबार सी.जेड.एम.ए.
वन सदन, हैडो, श्री विजय पुरम

सूचना

F. No: 2-3/DBRAIT/AC/1321 Dated: 27/07/2026

डॉ. बी. आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, श्री विजय पुरम में एकेडमिक सेशन 2026–27 (ऑड सेमेस्टर) के लिए अलग–अलग डिप्लोमा प्रोग्राम में गेस्ट फैकल्टी (GL) और पार्ट–टाइम इंस्ट्रक्टर (PTI) की भर्ती के लिए 01 अगस्त 2026 को वॉक–इन इंटरव्यू (डेमो थ्योरी और प्रैक्टिकल) रखा गया है।

योग्यता, इंटरव्यू के शेड्यूल और डेमो के विषयों की जानकारी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट https://dbrait.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रिज़्यूम और सभी शैक्षिक व अनुभव प्रमाण–पत्रों की प्रति साथ लाएँ। साथ ही, वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल प्रमाण–पत्र भी लाने होंगे। किसी भी सवाल के लिए उम्मीदवार इंस्टीट्यूट के एकेडमिक सेल से वर्किंग डेज़ में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच फ़ोन नंबर 03192–259818 पर संपर्क कर सकते हैं।

डीन (अकादमिक), डीब्राइट

ग्राम पंचायत का कार्यालय, श्याम नगर, स्वराज द्वीप, दक्षिण अण्डमान, श्री विजय पुरम

ई–निविदा सूचना

सं. 1–7 / एसएनजीपी / एसजेडीपी / ई–टेंडर / 2026–27 / 156 दिनांक 25 / 07 / 2026

भारत की राष्ट्रपति की ओर से ग्राम पंचायत कार्यालय, श्याम नगर, स्वराज द्वीप, दो बोली प्रणाली यानी तकनीकी बोली और कंपनियों / फर्म / एजेंसियों / सहकारी समितियों / स्वयं सहायता समूहों से ई–खरीद आमंत्रित करता है। ग्राम पंचायत श्याम नगर के अधिकार क्षेत्र के तहत सरकारी और वाणिज्यिक संस्थानों से कचरा संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए जनशक्ति के साथ न्यूनतम 3 सीबीएम क्षमता वाले वाहन की तैनाती, एसडब्ल्यूएम क्लस्टर श्याम नगर तक।

स्वीकृत कंपनियां / फर्म / एजेंसियां ग्राम पंचायत श्याम नगर के अधिकार क्षेत्र के तहत सरकारी और वाणिज्यिक संस्थानों से अलग–अलग कचरे के संग्रह, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान के लिए जिम्मेदार होंगी।

निविदा दस्तावेज में निर्धारित कार्य का विवरण और दायरा, नियम और शर्तें आदि, https://eprocure.andaman.gov.in का उपयोग करके ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

1. निविदा की आवश्यकता

क्र.सं.	से आमंत्रित किया गया निमंत्रण	सेवाओं का विवरण
1	कंपनियां / फर्म / एजेंसियां / सहकारी समितियां / स्वयं सहायता समूह	ग्राम पंचायत श्याम नगर के अधिकार क्षेत्र के तहत सरकारी और वाणिज्यिक संस्थानों से एसडब्ल्यूएम क्लस्टर श्याम नगर तक कचरे के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए जनशक्ति के साथ न्यूनतम 3 सीबीएम क्षमता वाले वाहन की तैनाती

नोटः उपरोक्त आवश्यकता विभाग की आवश्यकता के अधीन किसी भी वृद्धि या कमी की आवश्यकता है।

2. निविदा की अनुसूची

क्र.सं.	व्यक्तियों	दिनांक और समय
1	अनुमानित लागत	रु. 26,40,000 / – (लगभग) (वार्षिक)
2	बयाना धन जमा	रु. 52,800 / – (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत)
3	ऑनलाइन बोली जमा करने की तिथि और समय ऑनलाइन शुरू होने की तिथि और समय	27 / 07 / 2026 के पूर्वाहन 9.00 बजे
4	बोली बंद करने की तिथि और समय	16 / 08 / 2026 के अपराहन 5.00 बजे
5	निविदा दस्तावेज	निविदा दस्तावेज ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eprocure.andamannicobar.gov.in देखा जा सकता है
6	तकनीकी बोली खोलना	17 / 08 / 2026 पर पूर्वाहन 10.00 बजे
7	वित्तीय बोली खोलना	तकनीकी बोली के बाद सूचित किया जाएगा
8	निविदा जमा करना	निविदा केवल http://eprocure.andamannicobar.gov.in पर ऑनलाइन जमा / अपलोड की जानी है
9	ग्राम पंचायत कार्यालय, श्याम नगर द्वारा स्वीकृति के लिए बोली की वैधता अवधि / बोली प्रस्ताव की वैधता।	निविदा खोलने की तारीख से 90 दिन।
10	निविदा खोलने का स्थान	ग्राम पंचायत का कार्यालय, श्याम नगर, स्वराज द्वीप
11	प्रदर्शन सुरक्षा	अनुबंध के मूल्य का 5 प्रतिशत जिसका मूल्यांकन निविदा को अंतिम रूप देने के बाद किया जाएगा।
12	अनुबंध की अवधि	अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर अधिकतम 06 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करें और निविदा के समापन समय से https://eprocure.andamannicobar.gov.in पहले वेबसाइट पर ऑनलाइन बोलियां जमा करें। बोलियां जमा करने में अंतिम समय में विफलता के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

प्रधान
ग्राम पंचायत श्याम नगर, स्वराज द्वीप

तकनीकी वस्त्रों से संबंधित कुल 59 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गएः केंद्र

नई दिल्ली, 28 जुलाई ।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के अंतर्गत भारत में तकनीकी वस्त्र शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों को सक्षम बनाने हेतु सामान्य दिशानिर्देशः निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों के लिए लागू किए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य देशभर के अधिकाधिक शैक्षणिक संस्थानों को तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रमों एवं विषय–पत्रों के संचालन के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।

इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्नातक (यूजी) एवं स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर तकनीकी वस्त्रों से संबंधित कुल 59 पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इसके अतिरिक्त, देशभर के विभिन्न तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त 47 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके माध्यम से प्रयोगशाला उपकरणों के उन्नयन तथा संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इन पहलों के लिए कुल 216.60 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

यह योजना नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के पात्र शिक्षण संस्थानों के लिए खुली है। हालांकि, उपर्युक्त दिशानिर्देशों के तहत नवरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा औद्योगिक मानव संसाधन के कौशल उन्नयन के उद्देश्य से "तकनीकी वस्त्रों में उम्मीदवारों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सामान्य दिशानिर्देश" को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में आवश्यक कुशल मानव संसाधन का विकास करना है। इसके अंतर्गत चार प्रमुख लक्षित समूहों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

NOTICE

E- File No. 4032/1331 Dated: 27/07/2026

The interview (demo theory and practical) for recruitment of Guest Lecturers and Part time Instructor in various Diploma Programs in the establishment of Govt. Polytechnic Diglipur for the Academic Session 2026-27 (Odd sem) is scheduled 04th August 2026. The details of qualifications, schedule for interview and demo topics can be downloaded from the institute website https://dbrait.andamannicobar.gov.in. The eligible candidates are informed to bring their resume along the duly self-attested copies of education qualification, trainings, experience, etc to the Academic Cell, DBRAIT. The candidates shall also bring their original documents at the time of resume submission for verification. For any queries candidates may contact Academic Cell, DBRAIT and Govt. Polytechnic Diglipur on all working days from 9.00 AM to 3.00 PM or can contact over phone no. 03192-210955.

Principal i/c
Govt. Polytechnic Diglipur

PRESS RELEASE

F No.DBRAIT/01-2026/004 Dated :27/7/2026

This is to inform all candidates who are provisionally eligible for the recruitment to various contractual posts at Government Polytechnic, Diglipur that the schedule of examination is :-

Date	Time	Exam	Venue
04/8/2026	10am to 12noon	CBT for lecturer (Civil, CSE, Maths	CBT Lab
05/8/2026	10am to 12noon	CBT for Lab Technician(Civil & CSE)	
06/8/2026 onwards	9am to 6pm	Skill Test for Lecturer& Technician (Civil & CSE)	Respective labs (CSE) and Civil Engg. Labs

Registered candidates will receive their hall tickets via email shortly. Please download, print, and carefully follow all instructions. Note that exam attendance does not guarantee selection final appointment is subject to meeting all eligibility criteria as per the Recruitment Rules (RR).

Chairman
(Recruitment Committee-GPD)

छोटे शहरों के एमएसएमई को मिलेगा 'कॉरपोरेट मित्र' का साथ, सरकार ने शुरू की नई पहल

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

केंद्र सरकार ने कहा है कि 'कॉरपोरेट मित्र' योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक एवं अनुपालन सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही यह योजना युवाओं को उद्योग से जुड़ा व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित पैरा–प्रोफेशनल तैयार करने पर भी केंद्रित है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, शिलांग ने अरुणाचल प्रदेश के युवाओं, छात्रों, एमएसएमई, पेशेवरों और उद्यमियों के बीच इस योजना के प्रति जागरूकता बयाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया।

सरकारी बयान के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से टियर–2 और टियर–3 शहरों के एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए तैयार की गई है, ताकि वे 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य में प्रभावी योगदान दे सकें। सरकार का मानना है कि यह पहल विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

योजना के तहत मान्यता प्राप्त 'कॉरपोरेट मित्र' स्थानीय उद्यमों को नियामकीय अनुपालन, वित्तीय प्रबंधन, कराधान, लेखांकन और कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसे गैर–प्रमुख व्यावसायिक कार्यों में पेशेवर सहायता देंगे। इससे एमएसएमई अपने मुख्य व्यवसाय, नवाचार और विस्तार पर अधिक ध्यान दे सकेंगे।

योजना के पहले चरण में देशभर में 2,000 प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 200 प्रतिभागी विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र से होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के उम्मीदवारों को पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन और समन्वय के लिए IICA शिलांग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह संस्था राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर योजना के संचालन में सहयोग करेगी। सरकार के अनुसार, कॉरपोरेट मित्र योजना एमएसएमई के लिए एक मजबूत सहायता तंत्र विकसित करेगी। इससे छोटे उद्यमों को प्रशिक्षित, मान्यता प्राप्त और भरोसेमंद पेशेवरों की सेवाएं मिलेंगी, जिससे उनका कारोबार अधिक संगठित, टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।–(इनपुटःएजेंसी)

खेल मंत्री ने पदक विजेता झंडू कुमार को किया सम्मानित, 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि सौंपी

नई दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को सोमवार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की। पैरा पावरलिफ्टर ने ग्लासगो में पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग स्पर्धा में 190 किलोग्राम का सर्वश्रेष्ठ भार उठाकर कांस्य पदक जीता था।

सम्मान समारोह के बाद पैरा पावरलिफ्टर कुमार ने कहा कि वह रविवार देर रात दिल्ली पहुंचे थे और उतरते ही उन्हें संदेश मिला कि खेल मंत्री उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, खेल मंत्री मांडविया ने स्कॉटलैंड में मेरे अनुभव के बारे में पूछा और एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रेरित किया। मैं देश का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा।

बिहार के नालंदा जिले के हरनौत कस्बे से आने वाले झंडू कुमार का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। परिवार की मदद के लिए उन्होंने कभी सब्जियां बेचीं तो कभी ई–रिक्शा चलाया। जून 2023 में मुख्य पैरा कोच राजेंद्र रहलू ने उन्हें भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के गांधीनगर राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण के लिए चुना, जिसके बाद उनके करियर ने नई उड़ान भरी।

29 वर्षीय झंडू कुमार ने इससे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2024 में रजत और 2025 में स्वर्ण पदक जीता था। अब उनका अगला लक्ष्य 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची–नागोया में होने वाले एशियाई पैरा खेल हैं।

उन्होंने कहा, देश के शीर्ष नेतृत्व से मिलने वाला यह समर्थन खिलाड़ियों का मनोबल कई गुना बया देता है। मैं कुछ समय के लिए अपने घर जाकर परिवार से मिलूंगा और फिर गांधीनगर लौटकर एशियाई पैरा खेलों की तैयारी शुरू करूंगा। चीन के खिलाड़ी मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन मैं भारत के लिए पदक जीतने की पूरी कोशिश करूंगा।

राष्ट्रमंडल खेल 2026: शर्मिला ढांकर ने पैरा एथलेटिक्स में भारत को दिलाया स्वर्ण; शिल्पा ने जीता कांस्य

ग्लासगो, 28 जुलाई (हि.स.)।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की पैरा एथलेटिक्स टीम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला ढांकर ने स्थानीय समयानुसार सोमवार को महिलाओं की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया।

इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गईं।

शर्मिला ने फाइनल में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर शीर्ष स्थान हासिल किया और इतिहास रच दिया। एफ57 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए होता है, जिनके निचले अंगों में दिव्यांगता, अंगों की कमी या मांसपेशियों की शक्ति कम होती है।

इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के. शायला ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। शुरुआत में शिल्पा 7.26 मीटर के साथ चौथे स्थान पर थीं, लेकिन नाइजीरिया की यूकारिया इयियाजी का 8.19 मीटर का एकमात्र वैध थ्रो तकनीकी जांच के बाद फाउल घोषित कर दिया गया। इसके बाद शिल्पा तीसरे स्थान पर पहुंच गईं और उन्हें कांस्य पदक मिला।

यह पहली बार है जब राष्ट्रमंडल खेलों की किसी एक पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में भारत ने दो पदक जीते हैं। शर्मिला के ऐतिहासिक स्वर्ण और शिल्पा के कांस्य ने भारतीय दल के लिए यादगार दिन बना दिया। इन दोनों पदकों के साथ भारत का कुल पदक आंकड़ा 10 पहुंच गया है, जिसमें दो स्वर्ण, पांच रजत और तीन कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत फिलहाल आठवें स्थान पर है।

इतिहास के पन्नों में 29 जुलाई : नासा की स्थापना हुई, अमेरिका ने स्पेस रिसर्च के नए युग की शुरुआत की

नई दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)।

29 जुलाई विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इसी दिन वर्ष 1958 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसी कानून के माध्यम से दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के गठन का रास्ता साफ हुआ।

इस अधिनियम के लागू होने के बाद 01 अक्टूबर 1958 से नासा ने लगभग 100 मिलियन डॉलर की प्रारंभिक निधि के साथ अपना आधिकारिक कार्य शुरू किया। नासा ने उस समय की नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स की जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और एयरोस्पेस अनुसंधान का दायित्व संभाला।

स्थापना के बाद से नासा ने अंतरिक्ष विज्ञान में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। अपोलो मिशन के जरिए वर्ष 1969 में मानव को पहली बार चंद्रमा पर पहुंचाना, स्पेस शटल कार्यक्रम, हबल स्पेस टेलीस्कोप, मंगल ग्रह पर रोवर मिशन, वॉयेजर जैसे अंतरग्रहीय अभियान तथा आर्टेमिस मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं नासा की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं। आज नासा विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाओं में गिनी जाती है। इसके वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचारों ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा दी है, बल्कि मौसम पूर्वानुमान, संचार, पृथ्वी अवलोकन और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1567 – जेम्स षष्ठम को स्कॉटलैंड का राजा बनाया गया।

1748 – ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिये ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची।

1858 – यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने हैरिस संधि पर हस्ताक्षर किए।

1876 – साईंस ऐसोसिएशन की स्थापना।

1900 – इटली के राजा अम्बर्टो प्रथम की हत्या अराजकतावादी गेटानो ब्रेस्सी ने की थी।

1911 – मोहन बगान ने पहली बार आईएफ शील्ड जीती।

1914 – केप कॉड नहर को खोला गया था।

1920 – लिंक नदी बांध का निर्माण क्लमाथ पुनर्विचार परियोजना के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था।

1921 – एडॉल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता बन गए थे।

1931 – ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि सी. नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था।

1937 – जापानी सेना ने चीन के बीजिंग और तेनत्सिन शहरों पर कब्जा किया।

1957–अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी।

दवा कंपनियों की मार्केटिंग पर लागू किए गए नए सख्त नियम, डॉक्टरों को गिफ्ट और नकद लाभ देने पर रोक

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)।

केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों की मार्केटिंग में पारदर्शिता और नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (यूसीपीएमपी), 2024 के तहत कई सख्त प्रावधान लागू किए हैं। नए नियमों के तहत दवा कंपनियों को एथिक्स कमेटी फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज (ईसीपीएमपी) का गठन करना होगा, एथिक्स ऑफिसर नियुक्त करना होगा, शिकायतों के निपटारे और अपील की व्यवस्था करनी होगी, नियमों के पालन का स्व–घोषणा पत्र देना होगा और निर्धारित मार्केटिंग खर्च का खुलासा भी करना होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को संसद में दी गई।

सरकार ने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर रोक लगाना और दवाओं के जिम्मेदार प्रचार को बयावा देना है, जिसके तहत डॉक्टरों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाले संपर्क और प्रचार गतिविधियों को भी विनियमित किया गया है।

रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि फार्मास्युटिकल्स विभाग ने 12 अप्रैल 2024 को यूसीपीएमपी, 2024 अधिसूचित किया था, जिसने यूसीपीएमपी, 2015 की जगह ली। इसके बाद सितंबर 2025 में इस कोड में संशोधन भी किया गया।

उन्होंने बताया कि यूसीपीएमपी, 2024 में दवा कंपनियों द्वारा नैतिक मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए कई संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें ईसीपीएमपी का गठन, एथिक्स ऑफिसर की नियुक्ति, शिकायतों के निपटारे और अपील की दो–स्तरीय व्यवस्था, नियमों के पालन से संबंधित स्व–घोषणा और निर्धारित मार्केटिंग खर्च का खुलासा शामिल है।

मंत्री ने कहा कि इस कोड में दवा कंपनियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच प्रचार गतिविधियों से जुड़े नियमों को भी और मजबूत बनाया गया है। वर्ष 2025 में किए गए संशोधनों के तहत कंपनियों को संबंधित पोर्टल पर हर साल अपने मार्केटिंग खर्च का विवरण भी जमा करना अनिवार्य किया गया है।

सरकार के अनुसार, इस कोड का मुख्य उद्देश्य दवा कंपनियों की अनैतिक मार्केटिंग पर रोक लगाना और डॉक्टरों के बीच दवाओं के प्रचार को जिम्मेदारी के साथ सुनिश्चित करना है। इसके लिए डॉक्टरों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली गतिविधियों के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश तय किए गए हैं।

नए नियमों के तहत दवा कंपनियां अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स और अन्य कर्मचारियों की गतिविधियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगी। साथ ही, किसी भी दवा कंपनी को डॉक्टरों या उनके परिवार के सदस्यों को गिफ्ट, नकद लाभ या हॉस्पिटैलिटी जैसी सुविधाएं देने की अनुमति नहीं होगी।

कोड के तहत दवा कंपनियों को यह भी स्व–घोषणा करनी होगी कि वे सभी नियमों का पालन कर रही हैं। इसके अलावा, कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (सीएमई) और कंटीन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट (सीपीडी) के लिए आयोजित कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप पर किए गए खर्च का भी खुलासा करना होगा। कंपनियों का स्वतंत्र, रैंडम या जोखिम आधारित ऑडिट भी कराया जा सकता है। शिकायतों के निपटारे के लिए दो–स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है, जबकि अपीलों का निपटारा फार्मास्युटिकल्स विभाग करेगा।–आईएएनएस

रक्षा मंत्री ने तटरक्षक बल के लिए दो बड़े नीति सुधारों की घोषणा की

नई दिल्ली, 28 जुलाई (आईएएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के अधिकारियों और उनके परिवारों के हित में दो महत्वपूर्ण नीति सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले तटरक्षक कर्मियों के परिवारों को अनुग्रह राशि और अन्य लाभ अविलंब कराना है।

रक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले पांच दशकों में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियानों तथा तटीय निगरानी में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया कि ये नई नीतियां तटरक्षक बल का मनोबल बयाने के साथ उसकी ऑपरेशनल क्षमता को भी और मजबूत करेंगी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में स्वर्ण जयंती की ओर बय रहे भारतीय तटरक्षक बल को आधुनिक, सक्षम और भविष्य के लिए तैयार समुद्री सुरक्षा बल बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षामंत्री द्वारा जारी पहली नीति के तहत भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारियों की भर्ती और सेवा संबंधी व्यवस्था को पूरी तरह लैंगिक–तटस्थ बनाया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार महिलाओं को अब पुरुष अधिकारियों के समान लघु सेवा नियुक्ति और स्थायी नियुक्ति दोनों में भर्ती का अवसर मिलेगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी लघु सेवा नियुक्ति का प्रावधान खोला गया है।

प्रशिक्षण के शुरुआती चरण से ही महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलेंगे। पहले से स्थायी नियुक्ति पर कार्यरत महिला अधिकारियों को पात्रता पूरी करने पर उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में शॉर्ट सर्विस नियुक्ति पर कार्यरत महिला अधिकारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर स्थायी नियुक्ति में परिवर्तित होने का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह फैसला नारी शक्ति को बयावा देने और समुद्री

सुरक्षा व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

दूसरी नीति ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों के परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले तटरक्षक कर्मी को अनुग्रह राशि देने के उद्देश्य से मृत मान लेने का अधिकार निर्धारित किया गया है। इससे अनुग्रह राशि और सेवा समाप्ति से जुड़े अन्य वित्तीय लाभ देने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और सरल हो जाएगी। वहीं लंबे समय तक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और परिवारों को कठिन समय में शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन सुधारों से ड्यूटी के दौरान अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लापता होने वाले कर्मियों के परिजनों को अनावश्यक प्रशासनिक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन नीति सुधारों की घोषणा नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन–2 में की गई। इस कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।–आईएएनएस

अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई–ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू

नई दिल्ली, 28 जुलाई। सरकार ने अठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में ई–ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि ई–ज़ीरो एफआईआर के तहत 12 हज़ार से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में ई–ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1 9 3 0 के ज़रिए जुड़े मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप ई–ज़ीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। संजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को ई–ज़ीरो एफआईआर को नियमित एफआईआर में बदलने के लिए तीन दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, सारांश जैन को पहली बार मौका, रवींद्र जडेजा की वापसी

नई दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान एक बार फिर शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है।

इस टीम में सबसे बड़ा आकर्षण मध्य प्रदेश के अनुभवी ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन का पहली बार टेस्ट टीम में चयन है। 33 वर्षीय सारांश को वॉशिंगटन सुंदर के हैमस्ट्रिंग चोटिल होने के बाद मौका मिला है। घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है। वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है। उन्हें जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया था।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन दोनों का चयन बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस मंजूरी मिलने पर ही प्रभावी होगा। दूसरी ओर, चोट के कारण पुनर्वास कर रहे नितीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह नहीं मिली है।

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 अगस्त से एसएससी, कोलंबो में होगा। भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था, जहां उसने मेजबान टीम का 3–0 से सफाया किया था।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम– शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन।

जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन का चयन फिटनेस मंजूरी के अधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवसः भारत में वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से घटती बाघों की संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, साथ ही जंगलों के पारिस्थितिक संतुलन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जंगलों में बाघ सुरक्षित हैं, तो इसका अर्थ है कि वहां का पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ और संतुलित है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में सफलता हासिल की है। सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहल, आधुनिक मॉनिटरिंग तकनीक, एंटी–पोचिंग अभियान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के कारण देश में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

यही वजह है कि आज दुनिया के अधिकांश जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों के टाइगर रिजर्व न केवल संरक्षण के केंद्र हैं, बल्कि वन्यजीव पर्यटन के लिए भी बेहद लोकप्रिय हैं।

आज दुनिया में सबसे ज्यादा जंगली बाघ भारत में पाए जाते हैं।

भारत में वैश्विक जंगली बाघों की आबादी का लगभग 75% हिस्सा है।

भारत के बाद रूस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी बाघ पाए जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या भारत की तुलना में काफी कम है।

भारत में बाघ संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था।

इसके बाद संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, वैज्ञानिक निगरानी और अवैध शिकार पर सख्ती से बाघों की संख्या में लगातार सुधार देखने को मिला।

भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं।

ये रिजर्व बाघों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा, प्रजनन

और संरक्षण के लिए बनाए गए हैं।

इनका प्रबंधन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और संबंधित राज्य सरकारें मिलकर करती हैं।

भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय टाइगर रिजर्व हैं–

जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड– भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान।

रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राजस्थान – बाघों की आसान साइटिंग के लिए प्रसिद्ध।

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश – उच्च टाइगर डेंसिटी के लिए जाना जाता है।

कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश – समृद्ध जैव विविधता और सफारी के लिए लोकप्रिय।

पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र – द जंगल बुक से जुड़ा क्षेत्र।

ताडोबा–अंधारी टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र, – वन्यजीव फोटोग्राफी का पसंदीदा स्थान।

नागरहोल टाइगर रिजर्व, कर्नाटक – दक्षिण भारत के प्रमुख टाइगर आवासों में से एक।

बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक – नीलगिरि बायोस्फीयर का महत्वपूर्ण हिस्सा।

काजीरंगा टाइगर रिजर्व, असम – एक सींग वाले गैंडे के साथ बाघों के लिए भी प्रसिद्ध।

सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल – दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर का घर।

कौन थे जिम कॉर्बेट और क्यों उनके नाम पर पड़ा भारत के पहले नेशनल पार्क का नाम?

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

भारत में वन्यजीवों की बात हो और जिम कॉर्बेट का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक समय था जब पहाड़ों पर रहने वाले लोग उनके नाम से ही राहत की सांस लेते थे। वे केवल एक मशहूर शिकारी ही नहीं, बल्कि प्रकृति से बेइंतहा प्यार करने वाले इंसान, एक बेहतरीन लेखक और वन्यजीव संरक्षण के बहुत बड़े समर्थक भी थे।

उत्तराखंड का खूबसूरत शहर नैनीताल कॉर्बेट की जन्मस्थली है। छोटी उम्र में ही सिर से पिता का साया उठ जाने के कारण उनकी मां ने ही उन्हें पाल–पोस कर बड़ा किया। पयाई–लिखाई नैनीताल के ही 'ओक ओपनिंग्स स्कूल' और फिर 'शेरवुड कॉलेज' से हुई। हालांकि, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ इतनी जल्दी कंधों पर आ गया कि वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर सके और छोटी उम्र में ही उन्हें नौकरी करनी पड़ी।

कुमाऊं के घने जंगल और ऊंचे पहाड़ कॉर्बेट के लिए घर जैसे थे। बचपन से ही वे घंटों जंगलों में वक्त बिताते थे। इसी आदत ने उन्हें प्रकृति के इतने करीब ला दिया कि वे जानवरों की आवाजें, उनके पैरों के निशान और जंगल के तौर–तरीके बखूबी समझने लगे थे। उनकी जंगल की समझ इतनी पक्की थी कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के भी वे जानवरों की हर हलचल का सटीक अंदाजा लगा लेते थे।

बीसवीं सदी की शुरुआत में उत्तराखंड के चंपावत इलाके में एक आदमखोर बाघिन का खौफ चरम पर था। लोगों ने डर के मारे खेतों में जाना, जंगल से लकड़ियां लाना और बच्चों को बाहर भेजना तक बंद कर दिया था। ऐसे मुश्किल वक्त में जिम कॉर्बेट ने मोर्चा संभाला। अपनी सूझबूझ, धैर्य और जंगल के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने 1907 में उस बाघिन को मार गिराया।

इसके बाद 1924 में, उन्होंने रुद्रप्रयाग के उस कुख्यात आदमखोर तेंदुए को भी ढेर कर दिया जिसने लंबे समय से

गयवाल के लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

जिंदगी के एक पड़ाव पर आकर कॉर्बेट की सोच पूरी तरह बदल गई। उन्हें यह अहसास हुआ कि कोई भी बाघ अपनी मर्जी से आदमखोर नहीं बनता। जब वे बूढ़े हो जाते हैं, किसी वजह से घायल होते हैं या उन्हें जंगल में अपना असली शिकार नहीं मिलता, सिर्फ तभी वे इंसानों की तरफ रुख करते हैं। इस सच्चाई ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए शिकार करना छोड़ दिया, अपनी बंदूक रख दी और बाघों व अन्य वन्यजीवों की तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हाथ में कैमरा थाम लिया।

भारत में वन्यजीव संरक्षण को कानूनी रूप देने में जिम कॉर्बेट का बहुत बड़ा हाथ है। साल 1936 में बने देश के पहले नेशनल पार्क, 'हेली नेशनल पार्क', के निर्माण में उन्होंने मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी निभाई। अपनी भौगोलिक समझ के दम पर उन्होंने पार्क की सीमाएं तय कीं। साथ ही, उन्होंने तत्कालीन गवर्नर मैल्कम हेली और स्थानीय प्रशासन को शिकार पर पूरी तरह रोक लगाने और जानवरों को बचाने के लिए कड़े नियम बनाने के लिए प्रेरित किया।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवसः क्यों मनाते हैं यह दिन और क्या है इसका इतिहास और महत्व

नई दिल्ली, 28 जुलाई।

हम प्रकृति को मां कहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि इसी ने हमें जन्म दिया है और हमारा भरण–पोषण भी यही करती है। लेकिन धीरे–धीरे हम हमारी मां की तरह प्रकृति को भी हल्के में ले रहे हैं, जिसका परिणाम आगे चलकर काफी गंभीर होने वाला है। वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों, पेड़ों, महासागरों और पहाड़ों के अलावा समृद्ध खनिज और अनेको सुविधा हमें प्रकृति से मिली है ताकि हम एक स्वस्थ्य और खुशहाल जीवन जी सकें। लेकिन अफसोस की हम इन्हें सम्भालकर रखने के बजाय इन्हें बर्बाद कर रहे हैं।

समय के साथ, मानव जाति ने प्रकृति से मिले संसाधनों को खत्म कर दिया है, वन्य जीवन को बर्बाद कर दिया है। यहां तक के जो हवा हमारे लिए जरूरी है, जिसमें सांस लेकर हम जीवित रहते हैं उसे भी प्रदूषित कर दिया है। इसके बावजूद नेचर हमें समय–समय पर संकेत देती रहती है और कहती है कि अब भी समय है सावधान हो जाओ। ऐसे में अगर हमने अब भी पृथ्वी और उसके संसाधनों की रक्षा नहीं की, तो बहुत देर हो जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी आज यानी 28 जुलाई, को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोगों को एक बार पृथ्वी के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाया जा सके।

हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रकृति संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। हर दिन हर किसी के छोटे–छोटे योगदान से, हम अपने ग्रह को बचा सकते हैं और उस प्रकृति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें विरासत में मिली है।

इस दिन का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं है।

हालांकि, समय के साथ, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं ने हमें यह बता दिया है कि पृथ्वी की हालत कितनी खराब कर दी है। अब समय आ गया है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें और प्रकृति को प्रकोप दिखाने का मौका न दें।

जलवायु परिवर्तन पिछले कई सालों से एक गंभीर मुद्दा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और विलुप्त होती रहीं प्रजातियां प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर रही हैं। ऐसे में नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आदतों और आराम की वजह से पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इस दिन नेचर को समझने और उसके हित में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा करने के लिए कईत तरह के कार्यक्रम और सेमिनार का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि, हमें बातों से ऊपर उठकर अपने–अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को निभाना होगा क्योंकि बूंद–बूंद से सागर बनता है।